



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 32-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 7, 2018 (SRAVANA 16, 1940 SAKA)

General Review

उद्यान विभाग, हरियाणा की वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 16 जुलाई, 2018

No. 1782.कृषि.II(5)-2018/10686.—

1. बागवानी का मनुष्य के भोजन में पौष्टिकता व आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त इसमें ताजे फलों/सब्जियों की स्थिति तथा निर्मित उत्पादकों के रूप में निर्यात के बहुत अवसर प्रदत्त है। बागवानी क्षेत्र का बहुत महत्व है तथा यह एक स्थाई आर्थिक गतिविधि बन गया है। विभाग के भरसक प्रयत्नों के फलस्वरूप फल, सब्जियों, फल तथा खुम्ब के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2. वर्ष 2015-16 में फलों के अन्तर्गत 60,915 हैक्टेयर क्षेत्र था जोकि वर्ष 2016-17 में बढ़कर 61596 हैक्टेयर हो गया। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 के दौरान फलों का उत्पादन 737,820 मी0 टन था जोकि वर्ष 2016-17 में 770,965 मी0 टन हो गया है।
3. सब्जी उत्पादन क्षेत्र में, हरियाणा, देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यह दिल्ली के निकट स्थित है। वर्ष 2016-17 के दौरान सब्जियों के अन्तर्गत 4,11,051 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया जोकि वर्ष 2015-16 में 4,10,740 हैक्टेयर था। वर्ष 2016-17 के दौरान सब्जियों का उत्पादन 61,80,430 मी0 टन हुआ, वर्ष 2015-16 में 61,56,880 मी0 टन था।
4. हरियाणा राज्य में वर्ष 2016-17 में मसालों के अन्तर्गत 11,651 हैक्टेयर क्षेत्र था तथा उत्पादन 78,175 मी0 टन हो गया है।
5. हरियाणा राज्य खुम्बी के उत्पादन की खेती में एक अग्रणीय राज्य है। वर्ष 2015-16 में 10,500 मी0 टन खुम्ब का उत्पादन हुआ था, जबकि वर्ष 2016-17 में बढ़कर 10,530 मी0 टन हो गया है।
6. फूलों की खेती के फलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि हुई है। जिसकी देश व विदेशों में भी बहुत मांग बढ़ रही है। वर्ष 2016-17 में फूलों के अन्तर्गत 5514 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया है।
7. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली वर्ष 2016-17 तक 79,106 हैक्टेयर में लगाई गई इस विधि को अपनाने वाले किसानों को 52.50-65 प्रतिशत केन्द्रीय एवं राज्य सहायता उपलब्ध कराई गई।
8. वर्ष 2016-17 उद्यान फसलों की प्रगति के लिए कुल मिलाकर बहुत उपयुक्त रहा।

चण्डीगढ़:

दिनांक 22 जून, 2018.

अभिलक्ष लिखी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग।

**Review of the Annual Administrative Report of Horticulture Department, Haryana
for the Year 2016-2017**

The 16th July, 2018

No. 1782.Agri.II(5)-2018/10686.—

1. Horticulture crops are high value crops providing much needed nutritious food to human beings. These commodities have great potential for export as fresh and value added products. Horticulture has gained importance as a separate, viable economic activity. With the sustained efforts of the Department, considerable progress has been made in fruits, vegetables, flowers and mushroom cultivation.
2. During the year 2015-16, total area under fruit cultivation was 60,915 ha. which rose to 61,596 ha. by the end of 2016-17. Similarly during 2015-16 the production of fruits was 7,37,820 M.T., which arrived to 7,70,965 M.T. by the end of 2016-17.
3. The State being in close proximity of Dehli is ideally suited for vegetable cultivation. During the year 2016-17 area under vegetables is 4,11,051 ha. from 4,10,740 ha. in 2015-16. During the year 2016-17 production of vegetables was 61,80,430 M.T. as against the production of 61,56,880 M.T. during 2015-16.
4. During the year 2016-17, total area under spices is 11,651 ha. And production is 78,175 M.T.
5. Haryana State is one of the leading State in mushroom production. During the year 2015-16 was 10,500 M.T. of mushroom production, which increased to 10,530 M.T. during 2016-17.
6. Cultivation of flowers amongst the farmers has become a remunerative venture, as there is a good demand in the national and international markets. During the year 2016-17, the area under flowers is 5514 ha.
7. Upto the year 2016-17 79,106 ha. Area has been covered under Micro Irrigation system in horticultural crops and the farmers were provided central and state assistance @ 52.50-65 for installation of Micro Irrigation System during the year 2015-16.
8. The year 2016-17 was overall favourable for various horticultural crops.

Chandigarh:
The 22nd June, 2018.

ABHILAKSH LIKHI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Agriculture and Farmers Welfare Department.